



अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ

केंद्रीय कार्यालय: "प्रभात निवास" पंजीकरण नंबर 2037
सिंगापुर प्लाजा, 164, लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-600 001
फोन: 2535 1522 वेब: www.aibea.in

ई मेल: chv.aibea@gmail.com और aibeahq@gmail.com

परिपत्र सं. 28/436/2022/7

25-1-2022

सभी यूनियनों और सदस्यों के लिए:

प्रिय साथियों,

एआईबीईए पदाधिकारियों की बैठक

एआईबीईए पदाधिकारियों की बैठक कल जूम एप के जरिए वर्चुअली आयोजित की गई थी। कॉम. राजेन नागर, अध्यक्ष, ने बैठक की अध्यक्षता की।

हाल की अवधि के दौरान स्वर्गवासी हुए नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद, बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

1. बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हमारा निरंतर अभियान
2. आगामी आम हड़ताल में प्रभावी भागीदारी

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अभियान जारी रखें: बैठक में यूएफबीयू के आह्वान पर 16 और 17 दिसंबर, 2021 को देशव्यापी हड़ताल में भारी भागीदारी के लिए हमारे सभी यूनियनों और सदस्यों को बधाई दी गई। बैठक में कहा गया है कि हमारे अभियान और संघर्ष कार्यक्रमों के कारण, इसे विभिन्न राजनीतिक नेताओं से बहुत अधिक राजनीतिक समर्थन मिला और हड़ताल का सरकार पर भी प्रभाव पड़ा। सरकार का निर्णय होने के बावजूद शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश नहीं किया गया था।

सतर्क रहें - बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू होगा: लेकिन बैठक में अभियान को जारी रखने के महत्व को रेखांकित किया गया क्योंकि सरकार का एजेंडा सर्वविदित है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि 1 फरवरी, 2022 से संसद के आगामी बजट सत्र को देखते हुए, हमें सरकार के आगे के कदमों का अनुमान लगाने के लिए जीवित और सतर्क रहना चाहिए। इसलिए बैठक ने हमारे सभी यूनियनों और सदस्यों

को गतिविधियों के लिए आगे के संघर्ष कार्यक्रमों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

प्रधान मंत्री को पत्र का समर्थन: बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एआईबीईए के प्रधान मंत्री को पत्र प्राप्त करने का कार्यक्रम जितना संभव हो उतने सभी राज्यों के व्यक्तित्वों और नेताओं द्वारा किया जाना चाहिए।

23/24 फरवरी 2022 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल: बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 और 24 फरवरी 2022 को आम हड़ताल के लिए औपचारिक नोटिस मज़दूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन के आह्वान पर शीघ्र ही आईबीए को दिया जाएगा। आम हड़ताल की मांगों के महत्व और जरूरत को समझाते हुए हमारे सदस्यों को हड़ताल में उनकी उत्साही भागीदारी के लिए तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ।

अभिवादन के साथ,

आपका साथी,



सी.एच. वेंकटचलम
महासचिव

मांगे

1. **नए श्रम संहिताओं को रद्द करें;** ईडीएसए का रद्दीकरण
2. **किसी भी रूप में बैंकों / सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण नहीं करना** और राष्ट्रीय मुद्राकरण नीति को रद्द करना
3. **एनपीएस रद्द करें और पुरानी पेंशन योजना बहाल करें;** कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करे
4. **संविदा मज़दूरों, योजना मज़दूरों को नियमित करे** और सभी को समान काम का समान वेतन।
5. संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद, मांगों के 6 सूत्री चार्टर को स्वीकार करें
6. गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपये की खाद्य और आय सहायता;
7. मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार;
8. सभी अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा;
9. आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना मज़दूरों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा;

10. महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन मज़दूरों के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं;
11. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए धन कर आदि के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करे ;
12. पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपचारात्मक उपाय।

